RAJYA SABHA

Friday, the 19th May, 1995/29th Vaisakha, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Sukhdev Prasad, a former Member of Rajya Sabha on the 18th May, 1995 at the age of 74.

Born at village Piparpanti in Gorakhpur district in Uttar Pradesh in March, 1921, Shri Sukhdev Prasad had his education at his native place. He took active part in the freedom movement and also participated in the Satyagrah Movement in 1942 and worked for the uplift of the weaker sections of the society.

Shri Sukhdev Prasad started his legislative career as a Member of the U.P. Legislative Assembly from 1952—57. He was a Member of the Rajya Sabha representing the State of Uttar Pradesh from April 1966 to April 1972, April 1972 to April 1978 and again from April 1982 to February 1988. Shri Prasad was also Deputy Minister in the Union Council of Ministers from 1973 to 1977 holding the portfolio of Steel and Mines. He was appointed Governor of Rajasthan in 1988

Shri Sukhdev Prasad was Member of the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Committee on Petitions, Rajya Sabha. During his membership of the Rajya Sabha, Shri Sukhdev Prasad evinced keen interest in the proceedings of the House especially those concerning social welfare measures.

In the passing away of Shri Sukhdev Prasad, the country has lost a noted social worker and an experienced Parliamentarian.

We deeply mourn the passing away of Shri Sukhdev Prasad

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the Members of the bereaved family our profound sorrow and deep sympathy.

सरदार सरोवर परियोजना

*621. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरदार सरोवर परियोजना का डिजाइन दोषपूर्ण होने के कारण जलाशय से निरन्तर जल रिसाव हो रहा है जो भविष्य में खतरनाक सिद्ध हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, लगता है कि सरदार सरोवर परियोजना के बारे में समाचार-पत्रों में जो भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट छपती रही है उसको पढ़ने तक की फुर्सत सरकार के पास नहीं रहती है, इस विभाग के मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी देखते हैं

उनकी उलझन तो मैं समझा सकता हूं लेकिन सरकार के अधिकारियों को पढ़ना चाहिए। अभी-अभी "नवभारत टाइम्स" में छपा है कि पहाड़ पर्यावरण अकादमी के भू-वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि सरदार सरोसर परियोजना का डिजाइन दोषपूर्ण है और उसके जलाशय से शुरु से ही रिसाव हो रहा है जोकि कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। उसी अकादमी और उसके भू-वज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि यह कोयला और भड़ौच के नजदीक पड़ता है जोकि पूरा का पूरा इलाका भूकम्प प्रभावित है साथ ही रबागांव परियोजना भी इसी श्रेणी में आती हैं वह बांध है और बहुत ही नजदीक पड़ता है। सभापति जी उन भू-वैज्ञानिकों ने यहां तक बताया है कि उपग्रह से जो जानकारियां मिली हैं, उससे तो भूकम्प की आशंका जलाशय से प्रभावित होने वाले भूकम्प की आशंका भी बढ गयी है। इसलिय मैं मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पहाड़ पर्यावरण अकादमी के भू-वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है या नहीं? इस रिपोर्ट के बार में अखबारों में जो खबरें छपी हैं, आपके विभाग को उसकी जानकारी हैं या नहीं?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAIYYA NAIDU): Mr. Chairman, Sir, the report of the geologists referred to by the hon. Member is not available with us and if the hon. Member could provide some details on this, we will definitely examine. I submit, Sir, that we have ...*(Interruptions)*...

श्री जनेश्वर मिश्र: सर ऐसे कैसे चलेगा? यह 15 हजार करोड़ की परियोजना है।

DR. BAPU KALDATE: You are not having it.

SHRI P. V. RANGAIYAA NAIDU: Let me complete the answer. Sir, we have appointed a panel of experts. It is called the Dam Safety Panel for Sardar Sarovar Project consisting of five experts, namely, Dr. Y. K. Murthy, Shri J. N. Tandon, Shri A. N. Singh, Shri V. R. Deora kar and Shri R. V. Chalapathi Rao. They are all eminent engineers and geologists, and they have been constantly reviewing the progress of the work and also the construction and the design. They have held so far 27 meetings including the latest one on 23rd to 28th March and they are submitting reports to the Government based on which the Narmada Control Authority and also the Narmada Project Construction Committee are taking decisions and all step are being taken to ensure the safety of the dam.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी हमने जो सवाल पूछा हैं उसका जवाब बिलकुल नहीं आया है। यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी ही है अभी मैं सैकण्ड सप्लीमेंटरी पर नहीं आया हूं। मैंने पूछा है कि कोयला और भड़ौच का इलाका प्रभावित क्षेत्र है और नव गांव बांध परियोजना भी उसी श्रेणी में आती है?

MR. CHAIRMAN: You want to know the possibility of an earthquake taking place there.

श्री जनेश्वर मिश्र: इसके बारे में सरकार के जो एक्सपर्टस हैं जिनकी कि 29-30 मीटिंग्स ये बतला रहे हैं उन लोगों ने यह बताया है कि नहीं बताया कि भूकम्प आने वाले इतने सीरियस किस्म के इलाके में यह इतनी खर्चीली परियोजना बन रही है और इस खतरे का इन्होंने एहसास ही नहीं किया है और न ही इस जवाब में चर्चा की है कि उस कमेटी में इनके किसी भी एक्सपर्ट ने ऐसा बताया या नहीं बताया?

SHRI P. V. RANGAIYYA NAIDU: No, Sir, we have not received any reports regarding the danger of earthquake to this dam. We have implemented some designs for seismic observation. Out of 9 obser-

vations, 8 have been installed and construction of a building for the ninth station is in progress. We have already installed equipment for seismic observation. We are taking all possible steps to see whether there is any danger to this dam. Right now there is no such danger.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया । मुझे इस बात का अफसोस है । यह जवाब आना चाहियें । यह भविष्य में खोजकर दें या आप किसी तरह से इस पर चर्चा उठवाइए क्योंकि सन 76 में यह परियोजना चालू की गयी थी । और तब से राजनैतिक स्तर पर और वहां की, उस इलाके की जनता ने कई बार विरोध किया है । उस विरोध के बावजूद केन्द्र सरकार और तीन सूबो की सरकार यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार उस परियोजना को चालू करवाना चाहती है । पहले वर्ल्ड बैंक से रुपया मिलता था, कर्जा लेकर के यह परियोजना चला रहे थे । उस समय अमरीका और रूस में चूंकि तनातनी रहती थी दुनिया के नक्शे पर...

MR. CHAIRMAN: Please ask your question now.

श्री जनेश्वर मिश्र: जी, पूछ रहा हूं । तो अमरीका मदद किया करता था, अब यह वर्ल्ड बैंक ने रुपया देना भी बन्द कर दिया है । इसकी 1976 से 1995, बीस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आधी परियोजना अभी पूरी हुई है, जो लोग उजाड़े गये हैं, उनको बसाने का इन्तजाम नहीं किया गया है । अगर बीस साल बाद या तीस साल बाद, वर्ल्ड बैंक का रुपया न मिलने के बावजूद यह सिंचाई परियोजना या बड़ी परियोजना लागू होगी, तब तक देश की एक पीढ़ी गुजर जाएगी । सरकार से मैं साफ जानना चाहूंगा कि इन तमाम तकनीकी खामियों के बावजूद कब तक सरदार सरोवर परियोजना पूर्ण हो जायेगी ? क्योंकि यह 1976 से चल रही है, 19 साल, 20 साल हो गये, अभी तक जो लोग उजाड़े गये, उनके बसाने का इन्तजाम नहीं है, लोगों के डूबने की शंकायें अलग से आ गई हैं, कई खतरे हैं, उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, यहां पर, न पोलिटिकल...

MR. CHAIRMAN: You have made the point. Put your question.

श्री जनेश्वर मिश्र : यह कितने दिनों में पूरी होगी ? इसकी जानकारी सरकार से मुझे चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, when will it be completed?

SHRI JANESHWAR MISRA: It is scheduled to be completed around 2000 A.D.

श्री जनेश्वर मिश्र: कैसे हो सकता है ? यह 1976 से 1995 तक आधा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, तो यह कैसे कह रहे हैं कि पांच साल तक पूरा करेंगे ?

डा. बापू कालदाते : तीन साल में कह रहे हैं । ... (व्यवधान) ...

श्री जनेश्वर मिश्र : तीन साल में, जो कह रहे हैं, पूरा करेंगे, कैसे बोल रहे हैं ?

SHRI P. V. RANGAIYYA NAIDU: That is the schedule accepted for the time being provided funds are available.

SHRI JAGESH DESAI: Mr Minister, the Minister of Water Resources has assured that though the World Bank has stopped giving funds, the Government would fund it. So, you have to provide funds for that. He has given the assurance to the House. You cannot now say that funds will not be available.

SHRI P. V. RANGAIYYA NAIDU: The Government of India has agreed to reimburse to the extent of whatever the World Bank has stopped giving. We have

already got something from the World Bank. There is a balance of Dollars 167 million, that is, about Rs. 520 crores. The Government of India has agreed to reimburse that. The rest of it has to be raised by the participating States.

श्री राधाकिशन मालवीय : माननीय सभापति महोदय, नवागांव बांध पहले इस परियोजना का नाम था, बाद में सरदार बांध के नाम से इनका नाम रखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने वर्ष 1961 में इसका फाउन्डेशन किया था और 1976 स इस परियोजना के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। इस बांध की ऊंचाई 455 फीट हैं और इसमें मध्यप्रदेश के जो गांव हैं 193 पूरी तरह से इसमें डूब में आ रहे हैं।

श्री चिमनभाई मेहता : पूरी तरह से नहीं आ रहे।

श्री राधाकिशन मालवीय : पूरी तरह से आप गए नहीं हैं उधर। ... (*व्यवधान*) मेरी बात जरा आप सुन लें। .... (*व्यवधान*) पहले मेहता जी, हमारी बात सुन लो फिर कुछ बोलना। सर, मध्यप्रदेश के 193 गांवे पूरी तरह से लोगों की जमीन सहित गांव सहित डूब में आ रहे हैं इस परियोजना में मध्यप्रदेश को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हैं, देश हित में मध्यप्रदेश को फायदा हो या नहीं हो चाहे गुजरात को फायदा हो। गुजरात गवर्नमेंट ने यह अवार्ड पास किया कि मध्यप्रदेश के जो 33,000 परिवार डूब में आ रहे हैं उनकी हम पुनर्वसाहट करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

श्री राधाकिशन मालवीय 33,000 परिवार जो डूब में आ रहे हैं उनको हम सेटल करेंगे, प्रत्येक परिवार को हम 2 हेक्टर भूमि और उनकी बसावट के लिए मकान आदि के लिए 40,000/- रुपए उनको हम देंगे। जहां तक सवाल मध्यप्रदेश का हैं, जो पूरी तरह से डूब में 193 गांव आ रहे हैं कुछ लोगों को गुजरात में बसाया गया, मगर गुजरात गवर्नमेंट ने उनको पूरी तरह से सेटल नहीं किया। न पीने का पानी, न वहां स्कूल न वहां सड़क, न वहां कोई मकान। वहां से लोग वापस आ गए हैं।

MR. CHAIRMAN: Please ask your question... (*Interruptions*)

श्री राधाकिशन मालवीय : सर मेरा कथन यह है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने यह कहा हैं कि यदि 33 फीट इस बांध की ऊंचाई कम कर दी जाए तो हमारे 67 विलेज डूब से बच सकते हैं। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसकी ऊंचाई 30 फिट कम करेगी, इससे मध्य प्रदेश के जो आदिवासी इलाके हैं पूरी तरह से, उसमें 67 गांव डूब से बच सकते हैं ?

MR. CHAIRMAN: The question is about the reduction of the height? Would you reduce the height of this dam?

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: Sir, the question of reduction of the height, or whatever it may be, is pending before the Supreme Court. Till the matter is disposed of by the Supreme Court, we cannot say anything on this subject.

SHRI JAGESH DESAI: What is the view of the Government? (*Interruptions*) They should assure the House that the height would not be reduced.

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir, the matter is pending before the Supreme Court. (*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: What is the stands of the Government of India? It is for them to say that the height of the dam would not be reduced. (*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: The Award of the Tribunal is valid till 2025. Then only the question of review would come up. (*Interruptions*)

SHRI AJIT P. K. JOGI : The reduction In the height of the dam would be within the parameters of the Award. You would be saving 60 odd villages. Thousands and thousands of tribals have suffered.

MR. CHAIRMAN: I take it as your question. I won't call you afterwards. (*Interruptions*).

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir, that is the stand taken by the Government of Madhya Pradeh. They have put this before the five-man group which was appointed by the Government of India and also before the Supreme Court. As I said, the matter is pending before the Supreme Court. The Government is awaiting the decision of the Supreme Court.

श्री राधाकिशन मालवीय : अध्यक्ष जी, अगर इसकी 30 फिट ऊंचाई कम कर दें तो गुजरात सरकार को पानी में कोई कमी नहीं आएगी । गुजरात सरकार ने 460 किलोमीटर लम्बी नहर बना दी और उसके बाद भी उन्होंने डम को ऊंचा बनाया । मेरा कहना यह है कि अगर 30 फिट की ऊंचाई हम कम कर देते हैं तो 67 गांव डूबने से बच सकते हैं और सरकार को . . . (व्यवधान) . .

MR. CHAIRMAN: You are only explaining. You had already asked your question. (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It has not been answered, Sir. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Shri Chimanbhai Mehta. Mr. Mehta, you please just ask your question, instead of making a statement.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I will certainly do that, Sir.

MR. CHAIRMAN: I know it is an emotional question.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I am going by facts. 20-25 साल तक इसका कोई रिव्यू नहीं हो सकेगा यह नर्मदा ट्रिब्यूनल का एवार्ड है, यह बात मानकर चलनी पड़ेगी, वरना ट्रिब्यूनल एवार्ड के कोई मायने रहते नहीं है । अब दूसरी बात, जितने आस्टिस गुजरात में, महाराष्ट्र में किए गए, सबको पहले की स्थिति से ज्यादा अच्छी स्थिति में रिसेटल गुजरात में किया गया है, यह वर्ल्ड बैंक का आब्जेरवेशन है और दूसरों के भी आब्जरवेशन हैं । . . (व्यवधान) मैं बताता हूं कि वहां जिसके पास एक हैक्टेयर या आधा हैक्टेयर जमीन होगी, तो हमने उसे एक एक्टयर या दो हैक्टेयर दिया है . . (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : हम पांच आदमी वहां गए थे . . (व्यवधान) . . . .

श्री चिमनभाई मेहता : पैसा भी दिया गया है ।

MR. CHAIRMAN: I cannot allow a debate here. Please ask your question. Otherwise, please sit down.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I am asking the question, Sir.

MR. CHAIRMAN: Please ask your question.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: My Question to the hon. Minister is this. There is this talk of water continuously leaking from the pool and of faulty designing. Certain things are being talked about. In that context, I would like to know whether the designing is correct and is not faulty. That is my question. Is water continuously leaking, or, it is a scandalous propaganda which is going on against the Sardar Sarovar Project and, therefore, certain things are being said?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir, I have already said in my answer that there is no leakage. I can assure you that the design is not faulty. It has been testified by experts as correct and there is absolutely

SHRI GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Sir, the Sardar Sarovar Project is one of the important national projects. During the last monsoon, it sustained a great damage, posing a danger to the safety of the dam. In this connection, I would like to

know whether the repairs have been completed and whether the Government can assure the nation that there is no further danger to this project. Secondly, there is a great controversy, at present, about the height of the dam. I would like to know whether you are constructing the dam. taking into consideration that the height would be 83.3 metres. These are my two questions.

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Regarding the damage referred to by the hon. Member, I may state that during 1994, there had been some damage to the stilting basin, which is located on the down stream of the dam. The stilting basin is separated from the dam section of the construction joint and the stability of the dam section is independent of the stilting basin. The repairs have almost been completed and in a couple of months the remaining part of the repairs will be completed. We will ensure that there is no further damage...

श्री जनेश्वर मिश्र: लास्ट मानसून में डैमेज हुआ।

SHRI P. V RANGAYYA NAIDU: During the last damage the stilting basin was damaged. The work is going on and it will be completed within a couple of months and there will be no further damage in this regard in the coming monsoon.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the work be completed before the monsoon?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Yes, Sir, it will be completed by the next monsoon. Will you please repeat your question regarding the height of the dam?

SHRI GOPALRAO VITHALRAO PATIL: The construction work is going on taking into consideration 80.3 metres height or 83.3 metres height?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: It is 80.3 metres.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता

*622. श्री सुन्दर सिंह भंडारी:†
श्री शिवचरण सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघों की संयुक्त संघर्ष समिति की 25-सूत्री मांगों के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु सरकार द्विपक्षीय वार्ता करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जनवरी, 1994 में की गयी मांगों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आयुक्त के स्तर पर समय-समय पर विचार किया गया है और अधिकांश मांगें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री सुन्दर सिंह भंडारी द्वारा पूछा गया।